[Shrimati Vijoya Chakravarty]

Government should assume a direct responsibility to bring about a quick solution to the border issue and to ensure that no attempt is made to hold Nagaland Elections within Assam boundary. (*Interruptions)*

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): This is not fair.

यह तरीका ठीक नहीं है । आपने या तो इनको बोलने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, और अगर निमंत्रण दिया है, तो कांग्रेस पार्टी के डिस्टर्बेन्स के कारण उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिले, यह गलत बात है ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: We are not disturbing. I wanted to raise a point of order.

SHRI P. N. SUKUL: She has taken her seat. *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): .it is not the Central Government, but the Election Commission.. *(Interruptions)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आज इन्हें इलेक्शन कमीशन की याद आ रही है ।

जब हरियाणा के चुनाव का मामला उठाया गया था, तब इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आई ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : यह आप हमको क्या बता रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: Shri Advani.

Crisis in Cinema industry due to indefinite strike by U.P. Exhibitors protesting against exorbitant tax rates

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): Sir, I rise to draw the attention of the Government to the grave unrest prevailing in the film industry because of the issue of Entertainment Tax. Last Sunday, all cinemas in the country downed their shutters in support of the U.P. strike. In U.P. since 16th October, all cinemas have been on an indefinite strike because of the exorbitant rats of Entertainment Tax imposed on them, which is 150 per cent, which is, perhaps, the highest in the country. Sir, I wish to make three points in this connection. Firstly, it must be realised that with the advent of video, with the expansion of television and with video piracy coming in between, I think cinema has become essentially the poor man's entertainment. Therefore, this kind of an approach from the U.P. State Government and from various other State Governments is wrong, and needs to be revised.

Secondly, Parliament must be concerned with this matter. Since 1973-74, our Estimates Committee has been pursuing this issue. In its 58th report the Estimates Committee of the Lok Sabha had said, "The high rate of tax is pushing the cinema houses beyond the reach of the mon man. What is more disquieting is that no part of tax money collected is being ploughed back in the industry with the result that this policy of high taxation is driving the industry into the hands of those unscrupulous people from whom it needs to be rescued. The Committee feels that there is need for the rationalisation of the rate of Entertainment Tax." Various committees which have gone into the matter in details have suggested modes of rationalisation, 20 per cent, 25 per cent for the lower classes some of them 40 per cent. In Delhi to day *the* rate is 40 per cent. But 150 per cent is absurd. The third point I would like to make is that there is need for a national policy in this regard. It should not be left entirely to the States. The film industry is one of the most important industries in the country. It was in consideration of this that in 1977 a national film policy committee was constiuted. A working group was set up under Shri Shivram Karanth and that Shivram Karanth Committee submitted its report in 1980 or 1981, somewhere there. As far as I am aware, by and large, the Government is in agreement with the report. In that report the working group had said that the

prevalent rate of entertainment tax which on an average is 76 per cent of the basic admission rates should be considered excessively high by any standards. It made several recommendations in that regard as to how this should be reduced. I would like to appeal to the Government of India to intervene in this matter and not leave it to the State Government. Today, on the 11th. there is a big rally in Lucknow also on this issue. Perhaps many people from the film industry would be participating in it. It would be in the fitness of things if Mr. Panja, the Information and Broadca-ting Minister, takes an initiative and sees to it that the recommendations of the Karanth Committee on National Film Policy are accepted by all the States, including the U.P. Government. Thank you.

Reported social boycott of harijans, and violence in pandatrai village of Bilaspur district in Madhya Pradesd

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) सभापति महोदय, मैं एक ऐसी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो कई दिन पहले घट गई और वहां अब शांति स्थापित है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बात से या मेरे बयान से वहां की शांति भंग हो । मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का इलाका है और वहां पर एक बिलासपुर जिला है । उसके ठीक 45 किलोमीटर दूर पांडंतराई नाम का एक स्थान है एक कसबा है वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में चार आदमी मारे गए । सभापति जी मैं उस घटना का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के इलाके में पिछले दस वर्षों से बड़े पैमाने पर तनाव फैला हुआ है, सवर्ण लोगों में अनुसूचित जाति के हरिजन लोगों में तनाव है । इस तनाव का कारण यह है कि वहां पर सतनामी नाम का एक सैक्ट पैदा हुआ जो चमार लोग हैं, हरिजन लोग है और मोची लोग हैं उनका धंधा और पेशा सदियों से चमड़े का रहा है । छत्तीसगढ़ में उन लोगों की आबादी बड़े पमाने पर है । उन लोगों ने सतनामी नाम का एक आंदोलन चला करके ... (व्यवधान)

श्री भगतराम मनहर (मध्य प्रदेश) उसको तोड़-मरोड़ कर न बोलें ।

श्री सभापति : उनको खत्म करने दीजिए । आप अपनी बात संक्षेप में कह दें ।

श्री भगतराम मनहर: उनका क्या धंधा है आपको पता नहीं है । . . . (व्यवधान)

श्री सभापति: वह झगड़ा पैदा हो जायेगा वह बिलासपुर के हैं, यह हमारे जबलपुर और उत्तर प्रदेश के हैं ।

श्री शरद यादव : नहीं, मैं उनकी भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा । वहां सवर्ण और हरिजन के बीच बहुत पुराना झगड़ा हुआ है उस झगड़े का रूप और बड़ा करके जो घटना हुई उसमें चार आदमी मारे गये और उनकी गोली से हत्या की गई । सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हत्या बचाई जा सकती थी यदि कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई नहीं करती । वहां इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के दो गुट लड़ रहे हैं । उनकी लड़ाई के नतीजे में यह चार आदमियों की हत्या हो गई । यानी आधी पार्टी तो सवर्णों की तरफ हो गई है ।

श्री सभापति : अच्छा होगा हम लोग पार्टियों की बात न करें, नहीं तो फिर बात बिगड़ती है ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, अगर यह बात आपके ध्यान में नहीं लाई गई तो फिर वहां और विवाद बढ़ेगा और यह घटना आगे बढ़ सकती है ।

श्री सभापति : मैं केवल सिद्धांत की बात कह रहा हूं कि अच्छा होगा अगर हम पार्टियों का नाम इस सदन में न लें, अननसैसरली ।

श्री शरद यादव : ठीक है, सभापति जी मैं आपका आदेश मानता हूं कि । इस घटना के हो जाने के कारण जो मूल बात है जो ठीक बात है वह पीछे चली गई है यानी यह जो घटना है यह एक नाउ द्वारा सतनामी हरिजन लोगों के बाल बनाने से हुई और यह तनाव बढ़ा । तो जो मूल घटना है जो